



राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव

राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन

मुख्य अतिथि

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

दिनांक - 26 मार्च, 2025 | समय - प्रातः 10:30 बजे

स्थान - स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

30 हजार किसानों को
137 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति

किसान उत्पादक संगठन
(एफपीओ) के मेले का शुभारम्भ

योजनाओं के दिशा निर्देश

पॉली हाउस, सौर पम्प, कृषि उपकरण, प्याज भण्डारण, मधुमक्खी पालन इत्यादि हेतु 12 योजनाएं

बैल से खेती प्रोत्साहित करने हेतु योजना

किसान सम्मान निधि की राशि में 1,000 रुपए की वृद्धि

मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या दोगुनी

पशुधन स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क औषधियों व टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सशक्त किसान - समृद्ध राजस्थान

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

धनखड़ ने "जुडीशियरी" को नियंत्रण में लाने का अभियान पुनः शुरु किया

राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने राज्यसभा में दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई, इस मुद्दे पर

—डॉ.सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास पर कथित रूप से बेहिसाब नकदी पाये जाने के उग्र आरोपों के विवाद के बीच, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ न्यायपालिका को "नियंत्रण" में लाने के नये अभियान की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिये आज फ्लोर लीडर्स एक मीटिंग बुलाई थी। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा सदन के नेता जे.पी. नड्डा के साथ हुई मीटिंग के एक दिन बाद, धनखड़ के मन की बात उस समय बाहर आ गई, जब उन्होंने कहा कि "नेशनल जुडिशियल अपॉइन्टमेंट्स कमेटी (एनजेएससी) एक्ट" को दोहराने का यह सही समय है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आइयूपएल के हैरिस बीरन, जो आज की कार्यवाही को एक तरफ रखते हुये, इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहे थे, के नियम 267 के तहत दिये गये नोटिस को अस्वीकार करने के बाद, सभापति धनखड़ ने कहा, "मैंने फ्लोर लीडर्स को सुविधा की जानकारी लेने के बाद, आज अपराह्न 4.30 बजे उनकी

- धनखड़ का तर्क है कि दोनों सदनों (राज्यसभा व लोकसभा) द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव, जिसे पर्याप्त विधानसभाओं ने पारित किया, ऐसे प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार करके ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्या यह उचित निर्णय था?
- धनखड़ के अनुसार, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या संसद के दोनों सदनों व विधानसभाओं का कोई महत्व है, क्योंकि इन सभी संस्थाओं द्वारा पारित विधेयक को असंवैधानिक करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट।
- इस बार क्या धनखड़ का, जुडीशियरी द्वारा जर्जों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का प्रयास कुछ रंग लायेगा।

एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग का सुझाव विपक्ष के नेता ने दिया था तथा सदन के नेता ने इस सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। इस मीटिंग के समय की जानकारी सम्बंधित सांसदों को दे दी गई है। धनखड़ ने सदन में कहा, "मुझे यकीन है कि हमारी चर्चा बहुत उपयोगी रहेगी तथा कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका अपना अभीष्ट तभी दे पाती हैं, जब वे अपने-अपने क्षेत्र में अपना श्रेष्ठतम कार्य सम्पादन त्वरित गति से करती हैं।

उन्होंने एनजेएससी एक्ट का जिक्र करते हुये कहा, "मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु पर आपसे आपके सुझाव चाहता हूँ। भारतीय संसद ने एक अधिनियम बनाया था, जो आजादी के बाद एक दुर्लभ एकता की ओर उठाये गये एक ऐतिहासिक कदम के रूप में था तथा उसे राज्य विधानसभाओं की जरूरी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उस अधिनियम का क्या हुआ, इस पर आज पुनः चिन्तन करने की जरूरत है।" यह कहते हुये कि वे किसी मुद्दे पर जजमेन्ट होना नहीं चाहते, धनखड़ ने

कहा, "—लेकिन एक चीज, जिसे देश में व्यापक स्वीकार्यता मिली है, यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री बड़े पैमाने पर जनता के साथ साझा की जा चुकी है। मुझे यकीन है कि सारी चीजें हमें उपलब्ध हो जायेंगी।" उन्होंने कहा, "हम इस समय चौराहे पर खड़े हैं। मैं सदस्यों से गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे विचार करें। जो चीज संसद ने पारित कर की तथा विधानसभाओं ने जिसका समर्थन कर दिया, उसे किसी भी संस्था द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। धनखड़ ने कहा, "सदस्य इस पर विचार करें, इसीलिए, विपक्ष के नेता तथा सदन के नेता को बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह एवं अनुभव का लाभ लेते हुये, मैंने यह कदम उठाया है। और यह बड़ा ही दुर्लभ संयोग है कि सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष इस समय सदन के नेता तथा मुख्य विपक्षी दल के नेता सदन में विपक्ष के नेता हैं।" धीरे-धीरे पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह बंगाल के राज्यपाल के रूप में धनखड़ का अतीत हमें बताता है कि संवैधानिक पद पर होने के बावजूद, वे तटस्थ रहने के बजाय, वर्तमान सरकार के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा काम करते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पटवारी भर्ती परीक्षा धाँधली, दो पटवारी सस्पेंड

जयपुर, 25 मार्च। सिरोंही जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में हुई धाँधली के मामले में एसओजी की सूचना पर रेवदर ब्लॉक के दो पटवारी सस्पेंड किए गए हैं। राजस्व बोर्ड अजमेर के पत्र के आधार पर सिरोंही जिला प्रशासन ने डाक ग्राम पंचायत के पटवारी दिनेश कुमार पुत्र ठाकराराम और मगरीवाड़ा ग्राम पंचायत के पटवारी दिनेश कुमार पुत्र तुलाराम को निलंबित कर दिया है। रेवदर तहसीलदार मंजू देवासी ने बताया कि सिरोंही प्रशासन से पत्र आने

- सिरोंही जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा, 2021, में हुई धाँधली के मामले में दोनों निलम्बित पटवारियों पर परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिताने का आरोप है।

के बाद इन दोनों पटवारियों पर कार्रवाई की गई है। इन पर पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट बताने का आरोप था। एसओजी की जांच में दोनों पटवारियों के नाम सामने आए थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट बैठाए थे। जांच में आरोप पुष्टा पाए जाने के बाद एसओजी ने राजस्व बोर्ड अजमेर को पत्र लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। कलेक्टर अल्पसंख्यक चौधरी ने पत्र जारी कर दोनों पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। राजस्थान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या भाजपा व अन्नाद्रमुक एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे?

अन्नाद्रमुक के महासचिव मंगलवार को दिल्ली आये और फिर अन्नाद्रमुक के दो अन्य वरिष्ठ नेता भी दिल्ली पहुँचने से भाजपा व अन्नाद्रमुक के बीच में कुछ पकने की संभावनाओं की चर्चा बहुत गरम है

—लक्ष्मण वेंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 मार्च। ऐसा लगता है कि भाजपा और अन्नाद्रमुक के संबंधों को लेकर दिल्ली में कुछ खदबदा रहा है। गत वर्ष भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने जयललिता पर लगातार हमले कर अन्नाद्रमुक को गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। जयललिता पर हमले के कारण अन्नाद्रमुक के महासचिव ई. पलानीस्वामी ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा था। इससे द्रमुक विरोधी वोट बंट गए और तमिलनाडु व पुडुचेरी की सभी सीटें द्रमुक ने जीत ली थी। अब अन्नाद्रमुक महासचिव के दिल्ली आने से अटकलों का बाजार गर्म है कि भाजपा व अन्नाद्रमुक में फिर से गठबंधन हो सकता है, वरना द्रमुक की जीत तय है।

सूत्रों के अनुसार, अन्नाद्रमुक के दो अन्य ताकतवर नेता भी जल्दी ही दिल्ली आने वाले हैं। वे यहाँ अन्नाद्रमुक के कार्यालय का निरीक्षण करने आएंगे, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। संभावना है कि वे भाजपा नेताओं से भी मिलेंगे, पर अन्नाद्रमुक को अभी कुछ बाधाओं को हटाना जरूरी है।

- पिछले लोकसभा चुनाव के समय दोनों कुछ मनमुटाव के बाद गठबंधन तोड़कर अलग-अलग हो गई थीं तथा अलग-अलग ही चुनाव लड़ा था।
- नतीजा यह हुआ था कि द्रमुक विरोधी वोट बंट गया था तथा द्रमुक तमिलनाडु की सभी सीटों पर विजयी हुई थी।
- इस बार दोनों पार्टियाँ, अन्नाद्रमुक व भाजपा, द्रमुक विरोधी वोटों को बंटने नहीं देना चाहते। अतः दोनों पार्टियाँ, किसी तरह एक बार फिर एक साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं।
- पर, इस संभावना के बावजूद, दो बड़े मुद्दे, डीलिटिमेंशन व तीन भाषा फॉर्मूले पर आपसी समझौता करना पड़ेगा। अन्नाद्रमुक नेताओं की अचानक दिल्ली यात्रा इस प्रयास का ही अंग है।

इनमें सबसे प्रमुख है, त्रिभाषा फॉर्मूला अन्नाद्रमुक भी दो भाषा फॉर्मूला की पक्षधर है और इसे परिसीमन पर भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर दोनों दलों को विचार कर साझा रुख तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टालिन ने इन दोनों मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तमिलनाडु के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लेकर दिल्ली आ रहे हैं, जहाँ वे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ ज्ञापन देंगे। परिसीमन हुआ तो दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो जाएगी। अब अन्नाद्रमुक प्रमुख, दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यात्रा को 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से गठबंधन के प्रति लचीले रुख के रूप में देखा जा रहा है। अगर अन्नाद्रमुक से गठबंधन हो जाता है तो भाजपा को भी लाभ हो सकता है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण : एसओजी ने दो और गिरफ्तारियाँ कीं

एसओजी ने एन.डी. सारण से पूछताछ के बाद एक रेलवे स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल को पकड़ा है

जयपुर, 25 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए, वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण मामले में पालनपुर गुजरात रेलवे स्टेशन मास्टर सहित, बाड़मेर के ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि 30 जून 2024 को पुलिस थाना राजतलाब जिला बांसवाड़ा की ओर से 13 नवम्बर 2022 की दोनों पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा - 2020 कराई गई थी उक्त परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच एसओजी, राजस्थान जयपुर की ओर से की जा रही है। एसओजी ने इस मामले में बाड़मेर महाविद्यालय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश देव सारण को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सामने आया कि बाड़मेर निवासी टिमो हाल वनरक्षक को वन रक्षक भर्ती परीक्षा- 2020, 13 नवम्बर 2022 की द्वितीय

- ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल लिखमाराम, गिरफ्तार वन रक्षक टिमो का पति है, उसने अपनी पत्नी को उदयपुर में सॉल्व्ड पेपर पढ़ाने व वहाँ रूकवाने की व्यवस्था कराई थी।
- एन.डी. सारण ने यह भी बताया कि बालोतरा निवासी कंवरायाम, जो गुजरात के पालनपुर में स्टेशन मास्टर है, ने उसे टिमो को पेपर पढ़ाने के लिए 6 लाख रूपए दिए थे।

पारी का सॉल्व्ड पेपर उदयपुर परीक्षा केन्द्र पर पढ़ाने के एवज में बालोतरा निवासी कंवरायाम चौधरी जो गुजरात पालनपुर में स्टेशन मास्टर है, ने उसे 6 लाख रूपये दिये थे। ज्ञातव्य है कि टिमो को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस टिमो के पति लिखमाराम, जो बाड़मेर के चौहटन में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल है, को एसओजी ने सारण से पूछताछ के आधार पर पड़चंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह टिमो

को वन रक्षक परीक्षा का पेपर पढ़ाने के षडयंत्र में शामिल था। उसने अपने परिचित को बोलकर अपनी पत्नी टिमो को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पढ़ाने व रूकवाने की उदयपुर में व्यवस्था कराई थी। कंवरायाम चौधरी व लिखमाराम को जांच के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दो दिन का रिमाण्ड प्राप्त किया। ज्ञातव्य है कि आरोपित एन डी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ईद पर देगी सौगात-ए- मोदी

नयी दिल्ली, 25 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक मोर्चा ने रमजान के पावन अवसर पर हजरत निजामुद्दीन स्थित गालिब अकादमी में 'सौगात-ए-मोदी' किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी

- अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, सौगात-ए- मोदी में कपड़े, सेंवाई, खजूर, मेवे व चीनी दिए जाएंगे।

ने करीब 200 जरूरतमंद लोगों को 'सौगात-ए-मोदी' किट वितरित की। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनीस अब्बासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस. एम. अकरम, सूफ़ी संवाद अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. असलम, यासिर जिलानी, सौगात ए मोदी अभियान दिल्ली के प्रभारी इरफान सलमानी देहलवी, सह प्रभारी इमतियाज अहमद, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

9 से 5 की नौकरी को करें अलविदा, बने म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर।



अपने नए सफर की शुरुआत के लिए

संजित www.mfdkareinshuru.com

करें शुरू?

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादले के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल की

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए

प्रयागराज, 25 मार्च। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण की कोलीजियम की सिफारिश के विरोध में मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने गेट नम्बर तीन के बाहर टैन्ट लगाकर तबादले के विरोध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। घर में कथित तौर पर नगदी मिलने के आरोपों से घिरे न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ वकीलों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया। अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के बाहर "अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है", तथा "अधिवक्ता एकता जिंदाबाद" जैसे नारे लगाए।

- वकीलों ने हाई कोर्ट के बाहर धरना दिया, यज्ञ किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
- वकीलों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि जस्टिस वर्मा का किसी भी अदालत में तबादला नहीं होना चाहिए।
- उन्होंने कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम हमारी माँग नहीं मानता, हम काम पर नहीं लौटेंगे।

उन्होंने गेट के बाहर यज्ञ किया और वे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हालांकि अन्य लोगों को न्यायालय के अंदर जाने से रोक नहीं जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महासचिव विक्रान्त पाण्डेय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सदबुद्धि के लिए यज्ञ किया गया है और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा

है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हम किसी भी हाल में यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बैठने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार से फोटो एफिडेविट सेंटर भी बंद किए जाएंगे। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि

सोमवार शाम को न्यायालय बंद होने के बाद, न्यायमूर्ति वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तबादला होने की सूचना मिलने पर देर शाम उनके आवास पर ही एसोसिएशन ने पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाकर विचार-विमर्श किया। फिर वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय कोलीजियम द्वारा स्थानांतरण का निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाता है, तब तक यहाँ के अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। गौरतलब है कि 14 मार्च को दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास के एक कमरे में लगी आग में रुपए के बंडल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला- बाड़मेर में राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन

मु.मंत्री भजनलाल ने कहा, नारी का सम्मान समाज और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी

बाड़मेर/जयपुर, 25 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। कालीबाई भील, रानी पद्मिनी, मोराबाई, पना धाय और अमृता देवी जैसी महान महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। शर्मा मंगलवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए, इस बार राजस्थान दिवस अंग्रेजी कलेक्टर के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि नव संवत्, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को मनाया जा रहा है। इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष भीरेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है, इसीलिए राजस्थान दिवस समारोह का पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित किया है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने महिला सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं की चयनित लाभार्थियों से संवाद किया तथा महिला



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस समारोह के श्रृंखला में बाड़मेर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं को 5 हजार स्कूटी वितरित की।

समूहों को लगभग 100 करोड़ रुपये की आजीविका संवर्धन निधि का हस्तान्तरण और 5 हजार महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप का वितरण किया। साथ ही, उन्होंने स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सलेंस के अंतर्गत, 164 छात्राओं को चयन पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि आज 5 हजार स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है। शर्मा ने कहा कि किशनगढ़

में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पायलट बनाया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा एवं महिलाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की दृष्टि से निरंतर भर्तियां आयोजित कर रही है। इस बजट में भी हमने सवा लाख भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भर्तियों का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता के साथ कर रही है और हमारे एक साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय में एक के बाद एक पेपरलीक हुए और युवाओं के सपनों के साथ विश्वासघात हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। समारोह में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग राज्यमंत्री के.के. बिश्नोई, विधायक श्रीचंद कुपलानी, आदुराम मेघवाल, हमीर सिंह, प्रियंका चौधरी, अरुण चौधरी, ओट्टुसिंह भाटी, प्रतापपुरी, रविन्द्र सिंह भाटी, प्रभारी सचिव सुबीर कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग शासन सचिव डॉ. महेन्द्र सोनी सहित, बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

दिल्ली का एक लाख करोड़ रु. का बजट पेश

नयी दिल्ली, 25 मार्च। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए राशि आवंटित करने, बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर करने की योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कांड जारी करने, जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए, मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें 5100 करोड़ रुपये की राशि महिला समृद्धि योजना के लिए निर्धारित की गयी है।

यह पहला मौका है, जब दिल्ली विधानसभा में एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया

■ यह पहला मौका है जब इतना बड़ा बजट पेश हुआ है।

गया है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने 27 साल बाद मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता जब विधानसभा में बजट पेश करने के लिए खड़ी हुईं, तो भाजपा विधायकों ने मेजें थपथपा कर उनका अभिवादन किया और मोदी-मोदी के नारे लगाए। गुप्ता ने दो घंटा 18 मिनट तक बजट भाषण दिया, जो दिल्ली विधानसभा के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है।

जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच शुरू

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय आन्तरिक समिति ने उस कमरे की जांच की जहां आग लगने के बाद नकदी मिलने की खबर है

नयी दिल्ली, 25 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय आन्तरिक समिति ने मंगलवार को जांच शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि तीनों न्यायाधीश दोपहर करीब एक बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के 30, तुगलक-क्रॉस स्टैंड स्थित आधिकारिक आवास पर पहुंचे। वे करीब 45 मिनट तक न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और उन्होंने घटनास्थल का गहन

निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागु, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संघवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि उन सदस्यों ने उस कमरे की जांच की, जहां आग लगने के बाद कथित तौर पर नकदी मिली थी। हालांकि, न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया।

अपने जवाब में उन्होंने पहले दावा किया था कि जिस कमरे में आग लगी थी और जहाँ कथित तौर पर नकदी मिली थी, वह एक आउटहाउस था, न कि मुख्य इमारत, जहाँ न्यायाधीश और उनका परिवार रहता है। उन्होंने अपने जवाब में कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उस स्टोररूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई थी और मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ कि कथित नकदी हमारी थी। यह विचार या सुझाव कि यह नकदी हमारे द्वारा रखी या संग्रहित की गई थी, पूरी तरह से बेतुका है।

धनखड़ ने "जुडीशियरी" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। धनखड़, पिछले कुछ समय में, न्यायापालिका एवं कोलॉजियम व्यवस्था के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तभी से, 2014 से ही, वह स्वतंत्र न्यायापालिका के पर कतरने का हर संभव प्रयास करती आ रही है। जस्टिस वर्मा के निवास पर कथित रूप से बड़ी मात्रा में करेन्सी नोट मिलने

की दुर्घटनापूर्ण घटी घटना ने कई सवाल खड़े किये हैं, लेकिन इस घटना से सत्तारूढ़ पार्टी को न्यायापालिका पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के नवीनीकरण का सुअवसर निश्चित रूप से मिल गया है। सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रदीप माधुर ने कहा कि न्यायापालिका में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन राजनैतिक तंत्र भी, अगर उससे ज्यादा नहीं, तो उससे कम भ्रष्ट नहीं है।

सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रदीप माधुर ने कहा कि न्यायापालिका में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन राजनैतिक तंत्र भी, अगर उससे ज्यादा नहीं, तो उससे कम भ्रष्ट नहीं है।

क्या भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों दलों के समर्थकों को 2026 में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अभिनेता विजय के राजनीति में प्रवेश को ध्यान में रखना होगा, अभी वे नए हैं और वे किस नुकसान पहुंचाएंगे, यह देखना अभी बाकी है।

वन रक्षक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सारण ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 13 नवम्बर 2022 का सॉल्व्ड पेपर को परीक्षा से पूर्व पढ़ने के लिए अपनी ई-नोवा कार में 7 कैंडीडेट व पेपर हैंडलर को अपने ड्राइवर के साथ बाड़मेर से प्राइवेट बस स्टैंड उदयपुर भेजा था जहां से आरोपित कंवराराम जाट वांछित आरोपित जबराम जाट के कहने पर, अभ्यर्थियों ने आरोपित सांवलाराम जाट के किराए के मकान उदयपुर ले गया। सभी कैंडीडेटों को उनकी पारी के अनुसार वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 का सॉल्व्ड पेपर पढ़ाए गए, जो कंवराराम ने दिए थे।

जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जले होने का वीडियो सामने आया। उसके बाद 20 मार्च को न्यायाधीश वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

उच्चतम न्यायालय कोलॉजियम द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के प्रस्ताव के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा सोमवार को जनरल हाउस (आमसभा) बुलाकर महाभियोग लाने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही, न्यायाधीश के खिलाफ

प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई जांच कराने का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा। जनरल हाउस में प्रस्ताव पारित किया गया कि बार एसोसिएशन न्यायमूर्ति वर्मा का कहीं भी तबादला करने का विरोध करती है। प्रस्ताव कहता है कि न्यायमूर्ति वर्मा ने जो फैसले इलाहाबाद उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनाए हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए। बैठक में यह भी मांग की गई कि जांच

पटवारी भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों को निर्वाचित किया गया है। निर्वाचन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय उपाध्यक्ष अधिकारी कार्यालय, पिंडवाड़ा रहेगा और नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। अब तक 86 राज्यकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि 189 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। जैसे-जैसे जांच पूरी हो रही है, आरोपी कर्मचारियों को पदों से हटाया जा रहा है।

भाजपा ईद पर देगी सौगात...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कमाल बाबर, बबलु मंसूरी। फहीम सैफी, नईम सैफी, फैसल मंसूरी, सहित बड़ी संख्या में मोर्चे के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

इस मौके पर मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी के सफल नेतृत्व में भारत सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोर्चे के 32 हजार पदाधिकारी 32 हजार मस्जिदों से सम्पर्क कर 32 लाख जरूरतमंदों को "सौगात - ए - मोदी" किट के माध्यम से उपहार स्वरूप जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे।

किट में खाद्य सामग्री के अलावा कपड़े, सेवेई, खजूर, मेवे और चीनी शामिल होंगे। महिलाओं के लिए किट में सलवार-सूट का कपड़ा होगा, जबकि पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा शामिल है।

भाजपा का यह अभियान गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का भी एक प्रयास माना जा रहा है। प्रत्येक पदाधिकारी एक मस्जिद से मस्जिद कमेटी के सहयोग से 100 जरूरतमंद व्यक्तियों को चिह्नित करके उन तक "सौगात - ए - मोदी" किट उपहार स्वरूप पहुंचाने का काम करेंगे।

MARUTI SUZUKI

NEXA

GRAB IT BEFORE THE PRICE HIKE IN APRIL.

DRIVE HOME YOUR FAVOURITE NEXA CAR BEFORE THE PRICES GO UP.

CREATE. INSPIRE.

17th March 2025

Maruti Suzuki India Ltd. to hike car prices by up to 4% from April.

Maruti Suzuki India Ltd. announced on March 17th that it will increase car prices by up to 4% starting from April 2025, citing rising raw material and operational costs. The price hike will vary across different models.

3 years 100 000 km WARRANTY*
EXTENDABLE UP TO 6 YEARS

ONLY 06 DAYS LEFT

CONSUMER OFFERS OF UP TO ₹1 00 000*

EXCHANGE BONUS OF UP TO ₹1 00 000*

PER LAKH EMI STARTING FROM ₹1 470*.

ADDITIONAL SCRAPPAGE BONUS UP TO ₹15 000 IS AVAILABLE AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at 1800-200-6392 1800-102-6392

For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of financier. 3 years or 100 000 km - whichever is earlier. Scrappage offer valid for limited period only and is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 31st March 2025. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी 1/63 इंडस्ट्रियल एरिया फेस प्रथम, जालोर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाक्स, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाक्स, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय - जी 1/63, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय - जी जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 बृहत् कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूक, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908